विभिन्न युगों में भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास

भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास प्राचीन गुरुकुलों से शुरू होकर आधुनिक बहु-विषयक संस्थानों तक पहुँचा है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद कई आयोगों (जैसे NPE 1986) और परिषदों (NCTE) ने नीतियां बनाईं, जो अब NCTE Framework (NCFTE), दीक्षा पोर्टल (DIKSHA), और NEP 2020 के माध्यम से गुणवत्ता, व्यावहारिकता (इंटर्नशिप), और प्रौद्योगिकी (ICT) पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य चिंतनशील, कुशल और समग्र शिक्षक तैयार करना है, हालांकि अभी भी संख्यात्मक विस्तार और गुणवत्ता में सुधार की चुनौतियां हैं, जैसे कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का मुद्दा और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता।

1. प्राचीन काल में शिक्षक शिक्षा

प्राचीन भारत में शिक्षक शिक्षा का आधार गुरुकुल प्रणाली थी। इस काल में शिक्षक को 'गुरु' का उच्च स्थान प्राप्त था। शिक्षक बनने के लिए किसी औपचारिक प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं होती थी। गुरु अपने ज्ञान, अनुभव, तपस्या और आचरण के आधार पर शिक्षण कार्य करते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मज्ञान और सामाजिक कर्तव्यों का विकास था। शिक्षक शिक्षा मौखिक परंपरा, अनुशासन और जीवन मूल्यों पर आधारित थी।

2. बौद्ध काल में शिक्षक शिक्षा

बौद्ध काल में शिक्षा अधिक संगठित और संस्थागत रूप में विकसित हुई। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षक तैयार किए जाते थे। शिक्षक को 'आचार्य' या 'भिक्षु' कहा जाता था। शिक्षक बनने के लिए दीर्घकालीन अध्ययन, अनुशासन और प्रशिक्षण आवश्यक था। इस काल में संवाद, वाद-विवाद और तर्क पद्धति से शिक्षण दिया जाता था। नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान पर विशेष बल था।

3. मध्यकाल में शिक्षक शिक्षा

मध्यकाल में शिक्षक शिक्षा पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। शिक्षा मदरसा और मकतबों के माध्यम से दी जाती थी। शिक्षक को मौलवी या उस्ताद कहा जाता था। शिक्षक शिक्षा धार्मिक ग्रंथों पर आधारित थी। औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव था। शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक ज्ञान के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों के लिए योग्य व्यक्ति तैयार करना था।

4. ब्रिटिश काल में शिक्षक शिक्षा

ब्रिटिश काल में भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षक शिक्षा ने एक औपचारिक ढांचा प्राप्त किया: प्रारंभिक प्रयास (19वीं सदी): डेनिश मिशनरियों और विलियम एडम के प्रयासों से शिक्षक प्रशिक्षण शुरू हुआ। 1819 में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की।

वुड का घोषणापत्र (Wood's Despatch, 1854): 1854 के वुड्स डिस्पैच ने शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया। इसे भारतीय शिक्षा का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है। इसमें इंग्लैंड के तर्ज पर भारत में शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की गई। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए नॉर्मल स्कूल स्थापित किए गए।

हंटर आयोग (1882): इसने प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और सामान्य शिक्षा से शिक्षक प्रशिक्षण को अलग करने का सुझाव दिया।

सैडलर आयोग (1917): सैडलर आयोग (1917-19) ने शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस काल में शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली विकसित हुई। इसने कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग (Department of Education) खोलने का सुझाव दिया, जिससे शिक्षा को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली।

5. स्वतंत्रता के बाद शिक्षक शिक्षा

स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षक शिक्षा का क्रांतिकारी परिवर्तन, व्यापक और योजनाबद्ध विकास हुआ-

राधाकृष्णन आयोग (1948): इसने सुझाव दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को 'सैद्धांतिक' के बजाय अधिक 'व्यावहारिक' होना चाहिए।

मुदालियर आयोग (1952-53): इसने माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की सिफारिश की।

कोठारी आयोग (1964-66): इस आयोग ने शिक्षक शिक्षा को "राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण" बताया और सुझाव दिया कि व्यावसायिक प्रशिक्षण को सामान्य उच्च शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए।

NCTE की स्थापना (1973/1993): 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद' (NCTE) की स्थापना शिक्षक शिक्षा के मानकों को विनियमित करने के लिए की गई। NCERT, SCERT, DIET जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। B.Ed., D.El.Ed., M.Ed. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। 1993 में NCTE की स्थापना शिक्षक शिक्षा को नियंत्रित और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए की गई।

6. आधुनिक काल में शिक्षक शिक्षा

आधुनिक युग में शिक्षक शिक्षा तकनीक, नवाचार और शोध पर आधारित है। ICT, डिजिटल कक्षाएँ और ऑनलाइन प्रशिक्षण का प्रयोग बढ़ा है। शिक्षक को केवल विषय विशेषज्ञ नहीं बल्कि मार्गदर्शक, परामर्शदाता और राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा जाता है। समावेशी शिक्षा, मूल्य शिक्षा और व्यावसायिक दक्षताओं पर विशेष बल दिया जा रहा है।

NPE 1986: इसने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) की स्थापना की, जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए मील का पत्थर साबित हुए।

नई शिक्षा नीति (NEP 2020): वर्तमान में, 2026 तक के परिदृश्य को देखें तो NEP 2020 ने शिक्षक शिक्षा को पूरी तरह बदल दिया है।

4-वर्षीय एकीकृत बीएड (Integrated B.Ed): अब शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत डिग्री की ओर बढ़ रही है।

सतत व्यावसायिक विकास (CPD): शिक्षकों के लिए प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे के प्रशिक्षण को अनिवार्य किया गया है।

डिजिटल माध्यम: दीक्षा (DIKSHA) और स्वयं (SWAYAM) जैसे पोर्टल्स के माध्यम से शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है।

निष्कर्ष

भारत में शिक्षक शिक्षा का विकास समय के साथ निरंतर होता रहा है। प्रत्येक युग ने शिक्षक शिक्षा को नई दिशा दी है। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य एक कुशल, नैतिक और तकनीकी रूप से सक्षम शिक्षक तैयार करना है, जो समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके।

प्राचीन काल की अनौपचारिक गुरु-शिष्य परंपरा से लेकर आज की तकनीकी और अनुसंधान-आधारित शिक्षक शिक्षा तक का सफर लंबा रहा है। आज भारत का लक्ष्य शिक्षकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करना है। भारत में शिक्षक शिक्षा 'गुरु' से शुरू होकर अब 'प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशिक्षक' तक पहुँच गई है। आज का ध्यान केवल डिग्री पर नहीं, बल्कि कौशलों और व्यावहारिक शिक्षण क्षमताओं पर है। 2036 तक भारत की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य विश्व स्तरीय शिक्षकों का निर्माण करना है।